

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 राष्ट्र निर्माण की ओर

डॉ कृष्ण चंद्र चौधरी*⁹
गोविन्द कुमार**

सार

शिक्षा समाज एवं राष्ट्र को विकसित करने तथा प्रगतिशील बनाने का आधार है। मानवीय क्षमताओं का मूलभूत विकास शिक्षा से ही होता है। इसके द्वारा सम्पूर्ण जीवन के विकास की नींव रखी जाती है जो खुशहाल समाज का भविष्य तैयार करती है। समाज में समयानुसार परिवर्तन होना एवं उसे स्वीकार करने का ज़ज्बा शिक्षा द्वारा ही पैदा होता है। इसी प्रकार वर्तमान परिसंस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है। इसी परिवर्तनकारी एवं सुधारवादी दृष्टि का मूर्त रूप (एनईपी) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाहित है। हमारे राष्ट्र के लिए इस नीति का लागू होना बड़ा ही गर्व और हर्षोल्लास का विषय है। शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 तथा)

संशोधन 1992 के बाद आज़ाद भारत की यह तृतीय नीति 2020 है जो कि 34 वर्षों के एक लंबे अरसे के पश्चात् देश की शैक्षिक संरचना एवं प्रणाली को राह प्रदान कर रही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष सतत व में अपनाए गए 2015 विकास एजेंडा '2030 के लक्ष्य में 4 तक 2030 वैश्विक स्तर पर सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने' की बात कही गई है। यानी समान एवं समावेशी शिक्षा के लिए सामाजिकार्थिक रूप से वंचित व हाशिए पर रह रहे समूहों, बालिकाओं, सामाजिकच्छों पर जोर दिया जा रहा है। सांस्कृतिक पहचान वाले ब-इन्हीं लक्ष्यों के दृष्टिगत इस नीति के तहत 'सबके लिए शिक्षा' की आसान पहुंच, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही के आधारभूत स्तंभ सुनिश्चित किए जा रहे हैं और वैश्विक दृष्टिकोण का समावेशन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। इस नीति में विद्यालयी शिक्षा स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक कई अहम बदलाव हो रहे हैं, जिसमें कि मानवीय

*लेखक सहजानंद ब्रह्मर्षि महाविद्यालय, आरा वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के (विभागाध्यक्ष हैं और कोरोना को लेकर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला नोडल पदाधिकारी हैं। ये विगत वर्षों से शोध कार्य एवं व्यवहारिक लेखन में सतत रूप से 21) 802301 - सक्रिय हैं। भोजपुर बिहार। ईमेल: (krishna.nipccd@gmail.com मो. 7000595919 -न . शोधार्थी **, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा - 802301 (बिहार), भारत।)

विकास (प्रगति), ज्ञान प्राप्ति, गहन सोच, बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक लब्धि, सामाजिक लब्धि, भावनात्मक बोध, रचनात्मकता, संचार, उत्सुकता, संवेदनशीलता, मानव मूल्य, जीवन शिक्षा, सार्वभौमिक रूप से सीखना, जीवन पर्यंत शिक्षा और जिज्ञासा की भावना आदि के विकास पर अधिक जोर है। इसके स्वरूप का मसौदा डॉ कस्तूरीरंगन के अगुवाई में तैयार किया गया है। यह नीति पिछले दशकों से अधिक समय में हमारे देश 3, समाज की अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव के साथ प्रतिस्थापित हो रही है। शिक्षा का एक उद्देश्य आत्मज्ञान है। दूसरा उद्देश्य मानव के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, तीसरा उद्देश्य नागरिक के उत्तरदायित्वों को समझना और चौथा उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा। इस प्रकार प्राप्त करना है, व्यक्ति अपनी योग्यता को समझ कर तथा उसका सफल उपयोग करके शैक्षिक विकास करता है। अतः 21 वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तथा देश की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा के हर क्षेत्र में सुधार लाने की अपेक्षा है। इसलिए इस शिक्षा नीति में समतामूलक समाज, गुणात्मक, वहनीयसमान, समावेशी शिक्षा उत्तरदायित्व के साथ, की अवधारणा (4+3+3+5) शैक्षिक ढांचा, शिक्षा, भाषाई विविधता को बढ़ावा (भाषा सूत्र-त्रि) और भाषा के संरक्षण देने जैसे विषयों पर विशिष्ट रूप से ध्यान दिया गया है। इस नीति व्यवस्था की जगह विद्यार्थी आधारित व्यवस्था को पाठन की शिक्षक आधारित-में पठन ताकि विद्यार्थियों में रचनात्मक क्षमता, बढ़ावा दिया जा रहा है, तार्किक निर्णय, सामाजिक एवं भावात्मक कौशल विकास, अनुकूल सोचसृजनात्मक चिंतन एवं नवाचारी क्षमता को, भविष्यवादी शिक्षा विषयक व-मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा सके। बहु, गुणवत्तापरक शोध और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समान (अनुसंधान) उपयोग किया जा रहा है। सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रत्येक विद्यार्थी में निहित क्षमताओं को निखारना, सभी स्तरों पर सबकी समरूप पहुंच सुनिश्चित करना (ग्लोबल) स्तर से वैश्विक (लोकल) भारतीय शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय, स्तर पर पहुँचाना आदि इसके प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित है। अतः ये नीति 21 वीं सदी के 21 नए भारत की नींव तैयार करने वाली नीति सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है। अब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सोचने पर आधारित थी 'क्या', जबकि इस व्यवस्था वाले 'कैसे' में (नीति) विचार पर विशेष जोर दिया-सोचगया है।

भविष्य की रूपरेखा

इस नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारें देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग (जीडीपी) में विनिवेश करेंगी। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शिक्षा में भी प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र 6

सुधार हेतु काफी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है। साथ ही, विद्यालयों की आधारभूत संरचना में बहुत सुधार की आवश्यकता है क्योंकि भौतिक, पर्यावरण अच्छा होता है तो पढ़ने लिखने में भी मन लगता है।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है। इस नाम के बदलाव की मुख्य वजह शिक्षा की तरफ जनमानस का और विशेष रूप से मंत्रालय कार्यान्वयन की समय सीमा 'अधिक ध्यान खींचना (मिशन मोड) में जन-कल्याण के लिए कार्य कर सके ताकि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचना सुनिश्चित होने के साथ सुगम एवं सरल हो सके।

किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अन्य संसाधनों के समान ही उसके मानव संसाधन भी शिक्षित हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों के उपरांत देश की 75 वीं आवश्यकता के अनुरूप इस नीति की ज़रूरत हमेशा से महसूस की गई। इस संस्कृति और नीति में जहाँ एक तरफ भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृतिशक्ति-तर्क, परम्परा, डिजिटल साक्षरता, भारतवर्ष का ज्ञान, भावनात्मक बुद्धि का विकास, सामाजिक एवं मनोसामाजिक सोच आदि का विकास करना समाहित है वहीं दूसरी तरफ इन सभी के सृजन, उपयोगसंचरण और प्रसार की परिकल्पना भी, यह नीति करती है। अतएव शिक्षा व्यवस्था नए भारत के संविधान में मील का पत्थर साबित होगी। इसके : का अवसर प्राप्त होगा तथा राष्ट्र साथ बहुमुखी प्रतिभा को निखारने-द्वारा पढ़ाई के साथ को ब (खोज) नवोन्मेष और शोध, निर्माण का सपना भी पूरा होगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा देने के लिए यह नीति उपयोगी सिद्ध हो रही है। हर कक्षा में जीवनकौशल के विकास पर - थ में एक पूरी निवेश वीं कक्षा पास करके निकले तो उसके हा12 जोर होगा ताकि जब बच्चा सूची हो।

इस नीति का मकसद वीं सदी के आशानुरूप विद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को 21 अधिकसमावेशी, समग्र, लचीला बनाते हुए भारतवर्ष को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज तथा ज्ञान आधारित वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। जिससे छात्र अपने वैश्विक स्तर के दायित्वों को समझ सकें। आज के ज्ञानोन्मुख समाज में सम्पूर्ण विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसलिए, इसको कार्यान्वित करने और शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षकों की ज़रूरत होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के करोड़ 35

से ज्यादा विद्यार्थियोंके लिए लाख से ज्यादा 15 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं। पूरे देश के 1 विद्यालय, इस से ज्यादा विश्वविद्यालयों में 1000 हजार से ज्यादा महाविद्यालय और 41 शिक्षा नीति के सांचे से परिवर्तनकारी सुधार और दूरगामी प्रभाव से ही शिक्षा के नए स्वरूप का उदय हो रहा है।

10+2 की जगह शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की अवधारणा होगी लागू

बुनियादी मूलभूत चरण के/5 वर्ष- बाल्यावस्था मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें बच्चे के सम्पूर्ण जीवन के विकास की नींव रखी जाती है। नैसर्गिक रूप से बच्चा जन्म से ही सीखने के लिए तैयार होता है। इसमें विद्यालयी शिक्षा के प्रथम साल 5 शामिल हैं, जिसमें शालापूर्व शिक्षा के तीन साल एवं कक्षा एक और कक्षा दो समग्र रूप से शामिल हैं। पहले जहाँ सरकारी विद्यालय कक्षा एक से शुरू होते थे, वहीं अब वह शालापूर्व शिक्षा से शुरू होंगे। इस शिक्षा के पहले दो साल बच्चा किसी आँगनवाड़ी में शिक्षा (स्कूल-प्री) प्राप्त कर सकता है। बच्चे के जीवन के प्रथम 6 वर्ष उसके संपूर्ण विकास का मूलधार होते हैं। मस्तिष्क का विकास जन्म से पाँच साल के उम्र के बीच सबसे तेज गति से जिसमें होता है। 3 से 8 साल की उम्र के लिए, आधारीय चरण का सुझाव दिया गया है, जिसमें आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा को और अधिक (ईसीसीई) मजबूत आधार माना गया है। बहुआधारित सीखने हेतु तीन से छः वर्ष आयु वर्ग के स्तरीय खेल एवं खोजिए गतिविधि-सुरक्षित, या शालापूर्व शिक्षा के माध्यम से मुफ्त (बाल बाटिका) बच्चों के लिए आँगनवाड़ी एवं गुणवत्तापरक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। देश में 3-6 साल के करोड़ 10 बच्चे हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों के अलावा कक्षा 1 और 2 का तात्पर्य 6 से 8 आयु वर्ग के विद्यार्थियों से है। इस प्रकार पूर्व प्राथमिक के तीन साल और कक्षा 1 और 2 के दो साल, इसे पाँच साल तक की शिक्षा के तहत माना जाएगा। खेलकूद और क्रियाकलाप केंद्रित-पाठ्यक्रम के द्वारा भाषा कौशल और शिक्षणर खास ध्यान दिया अधिगम के विकास प-जाएगा।

इन कक्षाओं में अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, समस्या सुलझाने की कला, पहेलियाँ और तार्किक सोच, कला संगीत-नृत्य), ड्राइंग-पेंटिंग आदि, चित्रकला, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य कार्य, जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपसी सहयोग

और समूह में कार्य करने आदि को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अतः 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों द्वारा सीखने के लिए प्रेरक कौशल (नींव अवस्था), बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, कला, शिल्प, योग, खेल, भारत का ज्ञान के साथ ही समन्वित और टीम आदि गतिविधियाँ से समग्र विकास की कल्पना साकार की जा रही है।

बच्चों में मूल्यों को आत्मसात कराकर ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में बदला जाएगा। स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को नैतिक मूल्य जैसे सत्यता, अहिंसा, ईमानदारी, प्रतिबद्धता, सामूहिक कार्य, व्यक्तिगत, संगठनात्मक, राष्ट्रीय अखंडता और मानवीय मूल्य जैसे साथी-भावना, सहानुभूति, आपसी सम्मान, संवैधानिक मूल्य जैसे राष्ट्र व राज्य के प्रति मौलिक कर्तव्य, कानून का शासन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व-, बंधुत्व आदि की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा।

बच्चों का शारीरिक-संज्ञानात्मक विकास, सामाजिकनैतिक विकास-संवेगात्मक-, सांस्कृतिक विकास करना होगा। साथ ही, संवाद के लिए मातृभाषा या परिवेशीय भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना भी ईसीसीई का उद्देश्य होगा।

देश की सभी राज्य सरकारों के द्वारा सत्र 2025-26 तक प्राइमरी स्कूलों में कक्षा के तक 3 सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) Foundational Literacy & Numeracy प्राप्त करने हेतु ईसीसीई प्रणाली के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जा रही है। इस प्रणाली के परिणितिके रूप में मिशन शुरू हो चुका है। 'निपुण भारत'

प्रारंभिक चरण के 3 वर्ष- इस चरण में तक के 5 से 3 साल की उम्र या कक्षा 11 से 8 पाठन की व्यवस्था है। इसमें खेल केन्द्रित-बच्चों के पठन, अनुसंधान (खोज और गतिविधि) आधारित और परस्पर संवादात्मक सीखने पर जोर रहेगा। इस चरण में बच्चे के मानसिक स्तरानुसार, भाषा एवं संख्यात्मक कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कक्षा 5 तक स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा ही में शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी विद्यार्थियों को तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी और इन भाषाओं को तय करने का कार्य राज्य सरकार का होगा। इस दौरान, बच्चे अक्षर बोध (ककहरा का ज्ञान), अंक (ज्ञान-संख्या), रंग की अवधारणा, आकृतियां सीखेगा, पहेलियां हल करेगा, नाटक, कठपुतली के खेल, संगीत

अन्य हरकत से आनंददायी और रुचिकर सीखेगा जिससे सीखने की नींव तैयार होगी और शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित हो पाएगा ।

मध्य चरण के 3 वर्ष- यह चरण कक्षा छः से आठ तक के छात्रछात्राओं के लिए है । इस - विशेषज्ञों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं को समझाया जाएगा । यह -संरचना में विषय कार्य विज्ञान, गणित, कोडिंग, कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाएँ भारतीय एवं) किया जाएगा । इस हेतु आदि विषयों के शिक्षण से पूरा (विदेशी, एक से अधिक अनुभवात्मक सीखने के लिए वर्तमान समय में संचालित व्यवस्था एवं शिक्षाशास्त्र में - बदलाव लाया जा रहा है। इस चरण में विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा कि रट्टा लगाने पर। संगीत ,, कला एवं खेल विषय समान स्तर के होंगे। विद्यार्थियों में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कलाकौशल व दस्तकारी और रोजगारोन्मुख - शिक्षा का भी विकास किया जाएगा, यानी शिक्षा को भविष्योन्मुखी और कौशल उन्मुख बनाने के लिए रोजगार एवं उद्यमशीलता का कौशल विकसित करने पर खास बल दिया जाएगा। इसके साथ ही, कक्षा 6-8 (मध्य चरणमें बच्चों को कृषि और स्थानीय रूप से उपलब्ध (अन्य व्यवसायों के लिए 'एक्सपोजर' देना भी इस नीति का अंग है। अतः 2025 :तक, स्कूल , प्रशिक्षण और उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कमप्रतिशत शिक्षार्थियों को 50 कम-से-का परिचय एवं ज्ञान कराया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा

माध्यमिक चरण के 4 वर्ष- इसमें कक्षा या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा 12 से 9 विषयक अध्ययन शामिल -सम्मिलित रहेगी । इस स्तर पर सुझाए गए परिवर्तनों में एक बहु है जहाँ महत्वपूर्ण सोचछात्र उपलब्ध समझ और लचीलेपन पर ध्यान दिया जाएगा। जिससे-संरचना में से अपनी पसंद के अनुसार किसी भी विषय को चुन सके। चाहें वह तकनीकी के वाणिज्य के साथ विज्ञान या किसी अन्य वर्ग के विषय ही क्यों न हों । इस ,साथ कला चरण में आलोचनात्मक सोचव अधिक समग्रता के साथ पूछताछ, खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षा पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक संरचना के सभी स्तरों पर शिक्षणअधिगम - खोजपूर्ण ,सहयोगात्मक ,रचनात्मक ,को संवादात्मक बनाया जाएगा । कक्षाओं में रुचिकर गतिविधियों एवं आनुभविक सीखने को बढ़ावा दिया जाएगा । अब शिक्षकों की भूमिका बच्चों को 'कैसे सीखें' सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके जीवन में शिक्षा के महत्व को समझने में मदद करना, स्कूलों में बच्चों के सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिकभावनात्मक कल्याण की देखभाल करके समग्र रूप से विकसित करने में सहायता करने जैसी होगी। अतः वर्ष :2030 तक प्राइमरी स्कूल -प्री'

-से ग्रेड 12 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात-तक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के अंतर्गत शत ' सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। (जीईआर)

नवीन शिक्षा नीति में छात्र छात्राओं-के लिए सुनहरे भविष्य की परिकल्पना

इस शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा । - ऐसा करने से ही हमारा देश विश्व के अग्रणी और विकसित देशों के समान ही प्रगति कर पाएगा । इसके साथ ही, विद्यार्थियों की रुचि, ज्ञान, कौशल, अनुभव, विशिष्टता के प्रति विद्यालय से लेकर समुदाय तक सभी को संवेदनशील बनाया जाएगा। इस नीति में विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य हेतु कम से कम गुणों को विकसित करने की परिकल्पना 14 बुद्धिलब्धि -यथा ,पेश की गई है, संवेगात्मकलब्धि-, सामाजिकलब्धि-, भावनात्मकबोध-, रचनात्मकता, संचार, उत्सुकता, जिज्ञासा की भावना, संवेदनशीलता, मानवमूल्य-, जीवन-शिक्षा, सार्वभौमिक रूप से सीखना, समाजीकरण तथा जीवन पर्यंत शिक्षा। इन गुणों से 14 लैस बच्चे को वैश्विक नागरिक और विश्व मानव बनाने की परिकल्पना इस नीति में है । शास्त्रों में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शिशु को योग्य मानव बनाना है, दूसरा उसे उत्तम नागरिक तथा तीसरा परिवार का पालन-पोषण करने योग्य बनाना है । बहरहाल, अब लगता है कि हालात बदलेंगे ।

भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण

इस नीति में शालापूर्व शिक्षा और पहली से पाँचवीं कक्षा तक के पठन पाठन-हेतु मातृभाषा या परिवेशीय भाषा को अंगीकृत करने पर ज्यादा जोर दिया गया है । इसके साथ ही, कक्षा आठ एवं आगे की शिक्षा के लिए भी मातृभाषा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया (8) है। वैज्ञानिक डॉ कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई इस नीति में प्राथमिक स्तर पर त्रिबच्चा जन्म से ही भाषा सूत्र को अपनाने की बात की गई है ।- बाहरी दुनिया से मातृभाषा में संवाद करता है, इस वजह से मातृभाषा के प्रति मस्तिष्क की सक्रियता अन्य किसी माध्यम की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली रूप से होती है। यही कारण है कि इस नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जा रहा है । हर राज्य अपनी पसंदीदा भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होगा और उस पर इस संबंध में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा । स्कूल तथा और उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिये संस्कृत के साथ ही अन्य प्राचीन भारतीय भाषाएँ भी वैकल्पिक रूप में उपलब्ध रहेंगीलेकिन किसी भी भाषा को , विद्यार्थियों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा । बधिर विद्यार्थियों के लिये केंद्र और राज्य वि

सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा का पूरे -स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य देश में मानकीकरण किया जाएगा । यानी इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषाघर//राज्य की राजभाषा एवं अंग्रेजी और मानक कक्षा 6 से ऊपर को एक विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाने की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। अतइस नीति में पांचवीं कक्षा : तक और यथा संभव आठवीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी । भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे । विद्यार्थियों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत कक्षा के दौरान किसी भी समय भारत की 8 से 6 प्रोजेक्ट में भाग लेना होगा ।/भाषाओं पर एक आनंददायक गतिविधि

इसके अतिरिक्त पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें डिजिटल रूप से सीखने के मकसद को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी मंच बनाया जा रहा है । ईक्षेत्रीय भाषाओं में संचालित किए जायेंगे फिर 8 पाठ्यक्रम शुरू में- इनका दायरा बढ़ाया जाएगा साथ ही आभासीय प्रयोगशालाएं भी तैयार की जाएंगी । आ , प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे । अभी तक अधिकतर ऑनलाइन पाठ्यक्रम अंग्रेजी और हिंदी में ही उपलब्ध हैं ।

त्रि भाषाई सूत्र से-भाषाशक्ति में वृद्धि-

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व देने की बात कही गई है जो बच्चों के घर की भाषा को समझते हों । इससे बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए आधार भी मजबूत होगा। जहाँ घर और विद्यालय की भाषा अलगअलग है-, वहां दो भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है । पूर्व माध्यमिक शिक्षा -कक्षा)8के बाद (विदेशी भाषाओं की भी पढ़ाई होगी ।

यह बारबार सिद्ध हो चुका है कि हर बच्चा सहज भाव से अपनी मातृभाषा म-ें पढ़ाए जाने पर उसे तत्काल ग्रहण करता है । बच्चों को नर्सरी से कक्षा पांचवी तक की आरंभिक शिक्षा घर की भाषा में दी जाएदादी -दादा ,बहन-भाई ,बाप-जो वह अपने घर में अपने माँ , और दोस्तों से बोलना पसंद करता है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी देश तब ही तेजी से आगे बढ़ सकता है, जब उसके नौनिहाल अपनी जुबान में ही पढ़ाई शुरू करने का सौभाग्य पाते हों।

जीवन के अलगअलग क्षेत्रों में अपने लिए खास जगह बनाने वाली अनेक हस्तियां मिल - जाएंगी, जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही ग्रहण की। इनमें गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर से लेकर प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अंबेडकर शामिल हैं। गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की शुरुआती शिक्षा का प्रारंभ अपने कलकत्ता (अब कोलकाता) के घर में ही हुआ। उनके परिवार में बांग्ला भाषा ही बोली जाती थी। उन्होंने जिस विद्यालय में दाखिला लिया, वहां पर भी पढ़ाई का माध्यम बांग्ला ही था। यानी बंगाल की मातृभाषा में। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में बिहार के सीवान जिले के अपने गांव जीरादेई में ही हुई थी। बाबा साहेब की प्राथमिक शिक्षा सतारा, महाराष्ट्र के एक सामान्य विद्यालय से हुई और पढ़ाई का माध्यम मराठी भाषा था। साथ ही, जगदीश चंद्र बोस, एस एन बोस, दौलत सिंह कोठारी से लेकर अमर्त्य सेन और हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी तक बारबार इस बात को कहते रहे हैं - कि यदि देशको बदलना है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करना ही होगा। अतकता बहुभाषी : -और भाषा की शक्ति पर कक्षा 5 तक विशेष ज़ोर रहेगा तथा कक्षा तक 8, शिक्षा का माध्यम घरेलूपरिवेशीय भाषा होगी।

नवीन शिक्षा नीति में भारतीय भाषाएं

दुनिया भर के अनुभव इस बात के प्रमाण हैं कि किसी भी देश में बदलाव लाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है और प्रत्येक शिक्षा का वाहन भाषा होती है। वह भाषा जो सदियों के बाद उस समाज से निकलती है, गढ़ी जाती है, अपने को, उस सभ्यतासंस्कृति के साथ - एक शब्द को भरने में शताब्दी लगती है-आत्मसात करती है। एक जो मां की साँसों से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, दादीयों में होती है नानी की कहानी-; लोकगीत-, लोकसंस्कृति - व्यवहार में होती है। इसीलिए दुनिया भर में प्राथमिक शिक्षा को विशेष रूप में -और लोक अपनी भाषा में प्रदान करने की बकालत की गई है।

नवीन नीति का सबसे मजबूत पक्ष 'शिक्षा की भाषा' भी है। सरकार के पास भाषा संबंधित शिक्षा या पढ़नेपढ़ाने के प्रश्न पर हिंदी समेत अनेक भारतीय भाषाओं के प्रति एक स्पष्ट - दृष्टि एवं सोच है। क्या चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश में अपनी भाषा में नहीं पढ़ाते? यह भी समझने की जरूरत है। नीति के मंशानुरूप बच्चे यदि अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो आगे चलकर अन्य कोई भी विदेशी या भारतीय भाषाओं को जरूरी नहीं कि वह अंग्रेजी ही हो, को भी आत्मसात कर लेंगे और रचनात्मकता दे पाएंगे। भाषा के प्रश्न पर ही आजादी के

बाद कई आयोग बने और उन सब के पीछे एक ही वैज्ञानिक सोच थी कि स्थान व प्रदेश विशेष के लोग उस भाषा में अपनी शिक्षा, न्याय और पूरी व्यवस्था को प्राप्त कर सकें। कोठारी आयोग उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषा में की सिफारिश की स्तुति 1966 से 1964 प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर आज तक “दी जानी चाहिए कार्यान्वयन नहीं हो पाया। अतः स्थान दिया गया है इस नीति में भारतीय भाषाओं को अपना, जिससे आने वाले समय में आशान्वित परिणाम प्राप्त होंगे।

विद्यालय पाठ्यक्रम एवं अध्यापन कला से जुड़े सुधार

इस नीति में ऐसे पाठ्यक्रम और सीखने सिखाने की प्रणाली के विकास पर बल दिया जा रहा-
वीं सदी हेतु ज़रूरी कौशल 21 से पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए विद्यार्थियों में, है विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके तहत विद्यार्थियों को व्यावहारिक जानकारी से लैस करके उनका समग्र विकास किया जाएगा। आवश्यक ज्ञान प्राप्ति अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर, छ-अधिक ध्यान दिया जाएगा। छात्रात्राओं को अपने पसंदीदा विषय चुनने के कई खुले विकल्प दिए जाएंगे। नीति के मंशानुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर क्रियाकलापों के मध्य बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। कक्षा से ही पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुखी बना दिया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुता को भी सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में 2022 द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीईआरटी) तैयार की जा रही है।

‘परख’ एक पहल

हमारे देश में कई तरह के बोर्ड हैं और सबका स्तर अलग। इसके समाधान के लिए अलग है - छात्राओं के सीखने की प्रगति की बेहतर सूचना प्राप्त करने के लिए - इस नीति में छात्र नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही, इसमें विश्लेषणपरावर्ती बोध व तार्किक क्ष, मता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता को भी जांचने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। छात्र कक्षा 3, के स्तर पर विद्यालयी परीक्षाओं में 8 और 5 भाग लेंगे और इन परीक्षाओं का संपादन उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। वस्तु की ग-विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं विषयहनता को ध्यान में रखते हुए कक्षा की परीक्षाओं में परिवर्तन किये जा रहे हैं। इनकी बोर्ड की परीक्षाएं तो होंगी 12 एवं 10,

किन्तु इनके महत्व को अपेक्षाकृत कम कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं का संपादन साल में दो बार वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक (छमाही एवं सालाना) रूप में होगा। इससे विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षाओं का दबाव, डर एवं भय कम होगा। परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो और व्यावहारिक मॉडल तैयार हो सकें। विद्यार्थियों की रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विषयों की अवधारणा एवं ज्ञान को महत्व दिया जाएगा। पाठ्यक्रम को केवल मूल अवधारणाओं तक सीमित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित यह प्रमुख बदलाव वाले सत्र से लागू होने की 24-2023 प्रगति एवं क्षमता निर्, संभावना है। विद्यार्थियों की उपलब्धियोंधारण के मापन हेतु मानक मापदंड निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन/आकलन केंद्र परख (PARAKH- Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development) विद्यार्थियों की उपलब्धि व प्रगति के :की स्थापना की गई है। अतः (मूल्यांकन तथा उनके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने तथा सहायता प्रदान करने हेतु कृत्रिम मेधा आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

शिक्षण अधिगम-प्रणाली में सुधार

शिक्षा का प्रमुख वाहक शिक्षक होता है और शिक्षक के बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मूर्त - रूप दे पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए शिक्षकों का प्रभावशाली होना बहुत ज़रूरी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस नीति में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी एवं पूर्णतया पारदर्शी तरीका अपनाने पर बल दिया जा रहा है। समयसमय पर शिक्षकों के - प्रदर्शन का कई स्रोतों के-कार्यमाध्यम से आकलन कर पदोन्नति करने की मंशा व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के निर्धारण का कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। परिस्थितियों एवं बदलते परिवेश के अनुरूप शिक्षकों (एनसीटीई) को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करनेकी व्यवस्था की जाएगी। सन क्षिक दृष्टि से तक शै 2030 बहुविषयक व एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षक ,मजबूत बनने के लिए'वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री 4' का होना आवश्यक होगा। शिक्षकों हेतु पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 तक तथा फिर हर करने साल बाद इनकी समीक्षा 10 -विद्यार्थियों को सम्मानजनक जीवन (दिव्यांग) की बात नवीन नीति में कही गई है। विशेष यापन व शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष शिक्षकों एवं सामान्य शिक्षकों के लिए सेवापूर्व एवं सेवाकालीन मोड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा बहुविषयक शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। अंत में, यह नीति शिक्षकों का गौरव बढ़ानेसमाज में उनके सार्थक योगदान के ,

समुदाय संबंधों को मजबूत -स्कूल ,शिक्षकों की पहचान व शिक्षकों का समर्थन करने ,लिए करने, स्कूलपूर्व छात्र सहायता प्रणाली को सुदृढ़ बनाने-, शिक्षकों के बीच नैतिक और पेशेवर मानकों में सुधार करने, निरंतर सेवाकालीन शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार आदि करने हेतु प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष

हर बच्चा अद्वितीय है और राष्ट्र की संपत्ति एवं धरोहर है । लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राष्ट्रजो ,ण और उसकी उन्नति के कर्णधार बच्चे ही हैंनिर्मा- कुछ वर्षों बाद राष्ट्र के होनहार युवा होंगे । भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है । बसर कर रहे हैं उसमें -जिन परस्थितियों में रहते हैं या गुजर-हमारे देश में बच्चे जिन विविधता है । शिक्षा नीति में प्रत्येक बच्चे की अभिरुचि पर ध्यान देने की आवश्यकता पर विशेष ज़ोर है । अब विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार पढ़ाई करने का मौका मिलेगा । बच्चों के लिए विद्यालय जाना अब मनोरंजन के साथ साथ-‘खेलोपढ़ो-कूदो-’ पर आधारित होगा। इस नीति में बिना व्यावसायिक वीं सदी और गुणवत्ता से समझौता कि 21 प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुख शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है । ये सभी वीं सदी के सर्वांगीण दृष्टिकोण एवं समग्र कौशल का 21 क्योंकि शिक्षा नौजवानों में इस तरह क ,हिस्सा हैी चीजों को समाहित करती हैं । इनसे ही बच्चे वीं सदी के लिए जरूरी कौशल विकास21, बौद्धिक विकास, संचार, जिज्ञासा, खोज, रचनात्मकता, समस्या समाधान, विचारों की विविधता, वैचारिक गतिविधि, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तार्किक सोच और तर्कशक्ति विकसित करना आदि में योग्यता प्राप्त कर सकेंगे । वीं शताब्दी के कौशल21, गणितीय सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को एकीकृत करने के लिए पाठ्यक्रम को इसके अनुरूप बनाया जाएगा। शिक्षा नीति में की 4+3+3+5 संरचना का रूपरेखा, छठी कक्षा से व्यावहारिक प्रशिक्षण, रोजगारपरक शिक्षा, त्रिभाषाई सूत्र-, विद्यालय के पाठ्यक्रमपन कला और मूल्यांकन में सुधार आदि का दूरगामी प्रभाव अध्या , होगा । ऐसी शिक्षा बच्चों, किशोरों एवं युवा छात्रछात्राओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी - । यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र को दिशा देगी और वर्ष तक भारतीय शिक्षा प्रणाली 2040 21 : को सार्थक करेगी। अतः व्यापक बदलाव के लक्ष्यवीं सदी में, इस नीति का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाना है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में काफी विविधता है। फलतः तंत्र के-इसका लक्ष्य शिक्षा :गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना है और शैक्षणिक व्यवस्था का प्रबंधन करना है।

संदर्भ सूची

आईसीडीएस मिशन)2013); महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ।

चौधरी, कृष्ण चंद्र (2018); “प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल, विकास और शिक्षा”, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।

चौधरी, कृष्ण चंद्र 2019); “आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उभरती चुनौतियाँ और संभावनाएँ”, अप्रैल 2019, प्राथमिक शिक्षक, एनसीईआरटी, दिल्ली ।

चौधरी, कृष्ण चंद्र)2020) “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साँचे से होगा परिवर्तनकारी सुधार और दूरगामी प्रभाव”, प्राथमिक शिक्षक, एनसीईआरटी, एन। दिल्ली। - अंक)4, पृष्ठ 17-25, अक्टूबर 2020)।

यादव, पद्मा)2020) “प्राथमिक शिक्षा का बदलता स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020”, प्राथमिक शिक्षक, एनसीईआरटी, एन। दिल्ली। - अंक)4, पृष्ठ 26-35, अक्टूबर 2020)।

शर्मा, प्रेमपाल ” (2021) शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएँ”, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार; दिल्ली 2022 फरवरी ,, पृष्ठ .55-53

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन: टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एण्ड ह्यूमन टीचर-2009; दिल्ली नेशनल -काउंसिल फार टीचर एजुकेशन)2009)।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005; नयी दिल्ली, एनसीईआरटी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020; मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,(शिक्षा मंत्रालय)भारत सरकार।

Websites Links

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1642061> (Accessed 25.8. 2022)

<https://www.mhrd.gov.in/nep-new> (Accessed 26.8. 2022)

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/English1.pdf (Accessed 31.8. 2022)